(b) if so, what is the quantity of each imported during the last TWo Years, yearwise;

(c) what are the names of the companies which imported the above drugs and what are the names of the countries from which these were imported;

(d) wheher it is a fact that these drugs are produced in the country from basic stage;

(e) whether it is also a fact that production of these drugs are much higher than the total requirement of the country;

(f) whether it is a fact that Government have received a proposal to ban the imports of these drugs?

(g) if so. what are the details thereof and by when ban will be imposed on the imports of these drugs?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPA)ASWAMY) (a) to (c) Import of individual drugs is not being monitored by this Department..

(d) The stages of manufacture allowed for these drugs are given below: —

Metoprolol Tartarate—4 methoxy Ethyl Phenol

Albendazole -Meta -chloroaniline

Alprazolan—p-chloroquine

Fenbendazole—-2-nitro-5-ch!oro aniline

(e) This Department monitors production of only some important bulk drugs and formulations.

<f) to (g) Representations have been received for shifting of one item namely, Albendazole from OGL to 3(a) of the EXIM Policy. The same has been examined and action taken, taking into consideration various factors such as demand, production, number of manufacturers, a-vailability etc.

टिहरी बांध परियोजना की लागत

1521. श्री राम जेठमलानी: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध के निर्माण के लिये सरकार की वर्तमान निर्धारित लागत कितनी है ;

(ख) इस लागत के लिये क्या संसाधन तथा व्यवस्थाएं हैं ; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिये कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) टिहरी बांध परियोजना (टिहरी काम्पलैक्स का चरण-I) की अनुमानित लागत 1474 करोड़ रुपये है जबकि सम्पूर्ण टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स की लागत 3008.12 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) परियोजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है । परियोजना के विद्युत घटकों के लिये इनकी हिस्सेदारी अनुपात 75:25 के अनुपात में है । सिंचाई घटकों की सम्पूर्ण लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जायेगी । साबियत सुंध टिहरी जल विद्युत काम्पलेक्स के लिये 1000 मिलियन रुबल की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ।

(ग) टिहरी बांध चरण-I परियोजना के जून, 1997 तक पूरी किये जाने की आयोजना है ।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना

1522. सरदार जंगजीत सिंह अरोड़ा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ उद्योगों की स्थापना की गई है ;